नई शिक्षा नीति क्या लेकर आई?

• दिनेश कर्नाटक

'शैक्षिक दखल' के जनवरी 2020 अंक में हमने 'नई शिक्षा नीति की प्रतीक्षा' शीर्षक से नई शिक्षा नीति के मसौदे पर इसी स्तंभ में चर्चा की थी। अब जबकि हम जनवरी 2021 अंक को प्रकाशित करने जा रहे हैं तो नई शिक्षा नीति न सिर्फ आ चुकी है, बल्कि उसकी घोषणा के बाद उसकी ऐतिहासिकता को लेकर जो शोर-शराबा हो रहा था, वह भी शांत हो चुका है। शिक्षा नीति न सिर्फ शिक्षा से जुड़े हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आगे जाकर देश का मानस कैसा होगा इस दृष्टि से देश के सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस आलेख में हम शिक्षा नीति में क्या खास बातें कही गई हैं, इस पर चर्चा करने के बजाय मसौदे में जो कहा गया था, वह नई शिक्षा नीति में किस हद तक आ सका तथा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति को लेकर जो अपेक्षाएं थी, उस दिशा में नई शिक्षा नीति कितना सफल हुई है, इसकी विवेचना करेंगे।

सबसे पहले हम देखेंगे कि मसौदे के जो खास बिन्दु थे, क्या वे नई शिक्षा नीति में जगह बना पाये हैं? मसौदे में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव था। यह काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव था मगर नीति में इसे स्थान नहीं मिल पाया है। मसौदे में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को पूरी तरह से स्कूली शिक्षा के साथ एकीकृत करने की बात थी, मगर ऐसा नहीं होने जा रहा। नीति में बाल्यावस्था शिक्षा को आंगनबाड़ियों तथा पहले से मौजूद नर्सरी स्कूलों के माध्यम से संचालित करने की बात की गई है। मसौदे में शिक्षा के अधिकार कानून को कक्षा 12 तक ले जाने की बात की गई है, जबकि नीति इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहती। यह गोलमोल तरीके से कमजोर वर्ग के बच्चों को इसका लाभ देने की बात करती है।

मसौदे में जिस स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की गई थी, उसमें प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी संसाधनों से युक्त स्कूलों को एक परिसर में स्थापित करने तथा कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के एकीकरण की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव से सरकारी स्कूलों का स्तर सुधरता तथा उन्हें पुनर्जीवन मिलता। मगर नीति में दी गई स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा अलग तरह की है। यह 5 से 10 किमी0 के क्षेत्र में संसाधनों व शिक्षक-शिक्षिकाओं की शेयरिंग की बात करती है। इससे संसाधनों से जूझ रही सरकारी शिक्षा का संकट समाप्त होने के बजाय पूर्ववत बने रहने की आशंका बनी रहेगी।

मसौदे में कोचिंग तथा नंबरों की होड़ को समाप्त करने के लिए कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा को समाप्त करने की बात की गयी थी। नई शिक्षा नीति में कोचिंग तथा नंबरों की होड़ को गलत माना गया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बजाय बोर्ड परीक्षा को ऐसा बनाने की बात कही गई कि जिसमें पास होना कठिन न हो। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन को कक्षा 10 में भी लागू करने की बात की गई है। मसौदे में राज्य की पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था के नियामक के तौर पर 'राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण' के गठन की बात की गई थी। यह संतोष की बात है कि नीति में इसे स्वीकार किया गया है तथा उत्तराखण्ड राज्य ने इसे लागू करने में हामी भरी है। मसौदे में शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में 5 एसीपी देने की बात की गई थी, जबकि नई

साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, स्त्रियों के प्रति अपराध तथा भ्रष्टाचार हमारे समाज की ऐसी बुराइयां हैं, जिनसे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने तथा सवाल पूछने को प्रोत्साहन देने की बात करती है। नीति के आधार सिद्धांत में ऐसे अच्छे इंसानों के विकास की बात की गई है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य आधार हों। जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में योगदान दें।

शिक्षा नीति में शिक्षकों की पदोन्नति को उनके प्रदर्शन से जोड़ दिया गया है। हालांकि उत्तराखण्ड में शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में तीन पदोन्नति देने की बात कही जा रही है।

अब बात करते हैं मसौदे के उन बिन्दुओं के बारे में जिन्हें नीति में स्वीकार कर लिया गया है। इसमें स्कूली शिक्षा के वर्षों के 5+3+3+4 के रूप में पुनर्गठन की बात थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। 'नो डिटेंशन' नीति के दुष्परिणामों से निजात पाने के लिए कक्षा 3, 5 व 8 की सेंशस परीक्षाओं के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया है। कक्षा 6 से 8 तक बुनियादी दक्षताओं को शिक्षा से जोड़ने की बात को वर्ष में 10 दिन बगैर बस्ते के स्कूल आने तथा शिल्पकारों के साथ प्रशिक्षण लेने के रूप में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण तथा अंग्रेजी की अनिवार्यता के बजाय द्विभाषिकता की बात को भी स्वीकार किया गया है। उत्तर भारत में दक्षिण की एक भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के प्रस्ताव को नई शिक्षा नीति तीन में से दो भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाने के रूप में बदल दिया गया है। इससे पहले की तरह उत्तर भारत के राज्य किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को पढ़ाने के बजाय संस्कृत को पढ़ाते रहेंगे।

1968 की पहली शिक्षा नीति में समान शिक्षा का स्वप्न देखा गया था। बंटी हुई तथा भेदभाव पूर्ण शिक्षा भेदभाव पूर्ण समाज की ही रचना करेगी। दुर्भाग्य से आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था काफी ऊंचे-नीचे खांचों में बंट चुकी है। यह लोकतंत्र में समानता की अवधारणा के लिए उचित नहीं है। इसके अलावा शिक्षा में बढ़ता हुआ बाजारीकरण बड़ी चिन्ता का विषय है। इसने कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा दिया है। शिक्षा बेहतर मनुष्य के निर्माण के बजाय नौकरी की परियोजना बनकर रह गई है। इस लिहाज से नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रभावित करने वाला है। यह शिक्षा का उद्देश्य बेहतर मनुष्य का निर्माण तय करती है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा सार्वजनिक सेवा है तथा बच्चों का मौलिक अधिकार है। यह नीति सभी के लिए समावेशी, समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रस्तावित करती है। मगर इसी के साथ यह नीति शिक्षा में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने की बात करती है।

हाल के वर्षों में संसाधनों की कमी, शिक्षकों के रिक्त पदों तथा समुचित प्रबंधन की कमी जैसे कारणों से सरकारी विद्यालयों की साख काफी गिर चुकी है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहता, जबकि वहां पढ़ाने वाले शिक्षक उच्च स्तरीय चयन प्रक्रिया से चुनकर आते हैं। ऐसे में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि इस दिशा में नई शिक्षा नीति क्या कह रही है ?नई शिक्षा नीति लंबे समय से जीडीपी के 6 प्रतिशत को शिक्षा पर खर्च करने की मांग को मानती हुई दिख रही है। इसके साथ ही यह स्कूल को सम्मान व उत्सव का स्थान तथा सामाजिक चेतना का केन्द्र बनाने की बात कहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-प्राइमरी शिक्षा का अभाव होने के कारण बच्चे आगे की शिक्षा के लिए तैयार नहीं हो पाते थे तथा तीन साल से पांच साल की बेहद महत्वपूर्ण उम्र में उचित देखभाल न होने के कारण शुरूआती उम्र में ही जीवन की धारा में भटक जाते हैं। नई शिक्षा नीति प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का ढांचा व पाठ्यक्रम विकसित करने की बात कहती है।

हमारी शिक्षा का एक संकट बच्चों में बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान का न होना भी रहा है। प्राथमिक व जूनियर में पढ़ने वाले बच्चों में एक बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जो 5 या 8 में पढ़ते हुए भाषा पढ़ने-लिखने या गुणाभाग में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते। नई शिक्षा नीति बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय अभियान चलाने की बात करती है। यह वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करने को लक्ष्य बनाने की बात करती है। इसके लिए रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने, तात्कालिक पाठ्यक्रम निर्माण, सार्वजनिक व स्कूल पुस्तकालयों के विस्तार तथा पीटीआर को 30 : 01 करने की बात कही गई है। भारतीय भाषाओं के उपेक्षित होते जाने की स्थिति में नई शिक्षा नीति कक्षा 05 तक सरकारी व निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण की बात करती है। घर की भाषा व शिक्षण माध्यम भाषा में अंतर होने पर यह द्विभाषी एप्रोच व विज्ञान तथा गणित की द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों की बात कहती है। यह बच्चों के लिए एक भाषाई प्रोजेक्ट 'द लैंग्वेज ऑफ इंडिया' को भी करने की तजवीज करती है।

शारीरिक श्रम की उपेक्षा तथा शिक्षा का बुद्धि प्रधान होते जाना भी हमारी शिक्षा का एक बड़ा संकट है। शिक्षा का अर्थ मानो काम न करना तथा नौकरी पाना रह गया है। नई शिक्षा नीति कक्षा 6 से 8 तक व्यावसायिक शिल्प में दक्षता की बात करती है। इसमें वर्ष में 10 दिन बगैर बस्ते के बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकारों व शिल्पकारों के साथ काम करने की बात की गई है। 12 वीं तक शारीरिक शिक्षा, कला व शिल्प को सम्मिलित किया गया है। साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, स्त्रियों के प्रति अपराध तथा भ्रष्टाचार हमारे समाज की ऐसी बुराइयां हैं, जिनसे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने तथा सवाल पूछने को प्रोत्साहन देने की बात करती है। नीति के आधार सिद्धांत में ऐसे अच्छे इंसानों के विकास की बात की गई है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य आधार हों। जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में योगदान दें।

इस प्रकार नई शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा के बारे में काफी लुभावनी बातें करती है। देखना होगा कि यह सब बातें जमीन पर कब तथा कैसे उतरती है। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2021 की प्रतीक्षा करनी होगी।

❑❑❑